(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जी, हां ।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रथम श्रेणी वाले किसी भी आन्तरिक उम्मीदवार को, चाहे वह पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित हो अथवा न हो, जिसने पू०वि०पा० (गणित) के लिए आवेदन किया हो, दाखिले से इन्कार नहीं किया गया था । बाहर के उम्मीदवारों में से पिछड़ी जातियों सहित विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित बहुत से प्रथम श्रेणी के उम्मीदवारों को स्थान उपलब्ध न होने के कारण नहीं चुना जा सकता ।

इस सम्बन्ध में अक्तूबर, 1977 में, मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

Assistance for Upper Tapti Stage in Project

858. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 154 on 14th November, 1977 regarding Irrigation Projects on River Tapti and state:

(a) whether the Central Government is assisting the State Governments of M.P. and Maharashtra in completing the Upper Tapti Stage II;

(b) if so, the amount to be contributed by the Central Government; and

(c) whether Central Government propose to take up the matter with the State Governments to take up the Scheme soon as the area to be benefited by the scheme is mostly aboriginal area in both States?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). Report for the Upper Tapti Project—State-II, estimated to cost about Rs. 88 crores, and benefitting both Madhya Pradesh and Maharashtra States, as received from the Government of Maharashtra was examined in the Central Water Commission and comments sent to the State Government in March, 1976. Replies to these are still awaited and the Project therefore remains unapproved.

Irrigation is a State subject and Irrigation projects are executed and financed by the State Governments within the framework of their overall developmental programmes. Central assistance to State Plans is given in the forms of block loans and grants which is not related to any individual sector of development or project.

The question of requesting the States to give priority to the project would be considered after it is approved by the Planning Commission.

Number of pending House Building Loan Applications

859. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that for want of funds many house building loan applications are pending for approval;

(b) if so, what is the number of loan applications of Government employees pending for approval;

(c) what is the amount of loan involved and how many loan applications have been approved; and

(d) when the pending loan applications will be approved for payment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER): (a) and (b). Yes, Sir. The number of applications pending for approval of House Building Advance on date for want of funds is around 1900.

(c) and (d). In 1977-78, a total number of 13,194 applications involving a sum of Rs. 32.28 crores were approved till 31st January, 1978. The loan involved in the pending applications is approximately Rs. 6 to 7 crores. These applications will be cleared off by the end of the current financial year.

आयुध डिपों के वाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाना

861. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध डिपों के वाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाने का काम गत तीन वर्षों में किन-किन फर्मों से करवाया गया और उनमें से ऐसी कितनी तथा कौन-कौन सी फर्में हैं जो शिक्षित बेरोजगारों द्वारा चलाई जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

रक्षा मंत्रालय के वाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाने का काम

862. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रक्षा मन्त्रालय के कितने आयुध भंडारों की सप्लाई पूर्ति विभाग द्वारा की जाती है तथा क्या यह सत्य है कि रक्षा मन्त्रालय और आयुक्त भंडारों के सभी वाहनों के टायरों पर रबड चढ़ाने का कार्य टैन्डर द्वारा कराया जाता है और यदि हां तो ऐसे कितने भंडार हैं जो यह कार्य कराते हैं तथा उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या भाग (क) में पूछे गये कार्य को टैन्डर द्वारा कराया जाता है, यदि हां, तो कब-कब और गत तीन वर्षों के दौरान किन फर्मों से टैन्डर मांगे गये थे और उन्हें किन दरों पर काम दिया गया है ; और

(ग) क्या अधिकांश पार्टियों ने आपस में निश्चय करके ही एक जैसे टैन्डर दिये हैं यदि हां, तो किन फर्मों के टैन्डर एक समान थे तथा ऐसी कितनी फर्में थीं जिनकी दरें कम होने पर भी उन्हें काम नहीं दिया गया तथा उनके क्या नाम हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

किसानों को कृषि मूल्य आयोग का सदस्य बनाया जाना

863. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1978 को जयपुर में आयोजित राजस्थान किसान यूनियन की एक सभा में पारित प्रस्ताव में यह मांग की गई कि कृषि मूल्य आयोग के अधिकांश सदस्य अनुभवी किसान होने चाहिएं और इसका अध्यक्ष भी एक किसान होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) . इस मंत्रालय